हिमाचल

दैनिक भास्कर, शिमला, बुधवार 9 सितंबर, 2026

न्यूज ब्रीफ

नालागढ़ में फैक्ट्री प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

नालागढ़ | नालागढ़ के महादेव गौशाला के पास स्थित एक उद्योग के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस मौके एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान 'जन चेतना महादेव संघर्ष समिति' का गठन कर ज्ञान चंद ठाकुर को प्रधान चुना गया। ज्ञान चंद ठाकुर ने बताया कि फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं, दुर्गंध, गंदे पानी और कचरे से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों ने उद्योग द्वारा किए जा रहे अत्यधिक भूजल दोहन पर चिंता जताते हुए परिसर में मौजूद सभी बोरवेल और ट्यूबवेल की अनुमति की जांच करने की मांग की है। इसके अलावा, अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को हो रही समस्याओं को रेखांकित किया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से पानी, हवा और मिट्टी के सैंपल लेकर अधिकृत प्रयोगशाला से जांच करवाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की पुरजोर मांग उठाई है।

बीएसएल नहर में छलांग लगाने वाले गोविंद का दूसरे दिन भी सुराग नहीं

सुंदरनगर | सब्जी मंडी धनोटू के समीप बीएसएल नहर में छलांग लगाने वाले 43 वर्षीय गोविंद का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। सोमवार को नहर में छलांग लगाने के बाद से गोविंद लापता है। मंगलवार को सुंदरनगर पुलिस की टीम और एनडीआरएफ के जवानों ने नहर में सर्च अभियान चलाया, लेकिन दिनभर तलाश के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका। पुलिस को दी शिकायत में गोविंद के मामा विद्यासागर निवासी गांव डूमर, तहसील निहरी ने बताया कि उनका भानजा गोविंद मानसिक रूप से परेशान था। सोमवार को वह उसे दवा और चेकअप के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक ले गए थे। वापस लौटते समय सब्जी मंडी धनोटू में सामान लेने के लिए गाड़ी रोकी। इसी दौरान गोविंद गाड़ी से नीचे उतरा और अचानक बीएसएल नहर में चला गया। इसके बाद वह पानी में लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। सोमवार को स्थानीय स्तर पर तलाश करने के बाद मंगलवार को एनडीआरएफ के जवानों की मदद ली गई। लेकिन देर शाम तक गोविंद का कोई सुराग नहीं मिल पाया।

आपदा में कर्मचारियों का हौसला बढ़ाएं, नारेबाजी से बचें: विनोद सुल्तानपुरी

परवाणू | कसौली विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से बनी आपदा की स्थिति के बीच प्रशासन की कार्यप्रणाली के विरुद्ध ज्ञापन देने व विभिन्न विभागों के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद परवाणू में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इसी बीच विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए लोगों से उनका मनोबल बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के कर्मचारी दिन-रात राहत एवं पुनर्बहाली कार्यों में जुटे हैं और कई अधिकारी रात 2-3 बजे तक व्यवस्थाएं सामान्य करने में लगे हुए हैं। सुल्तानपुरी ने कहा कि जल शक्ति विभाग पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है जबकि राजस्व विभाग प्रभावित लोगों के घर-घर जाकर मदद कर रहा है। लोक निर्माण विभाग भी सड़कों की बहाली सहित अन्य कार्यों में जुटा है। भाजपा के ज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने कहा कि आपदा के समय विभागों के खिलाफ नारेबाजी करना राजनीति चमकाने की कोशिश है।

कॉलेज और पीजी के परिसरों को रैगिंग मुक्त बनाए रखने के लिए सतर्कता जरूरी: डॉ. भारती

हमीरपुर | डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान कॉलेज हमीरपुर में आज तक रैगिंग का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद कॉलेज, हॉस्टल एवं पीजी के परिसरों को रैगिंग मुक्त बनाए रखने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। कुछ दिनों में ही नया बैच शुरू होने जा रहा है। इसके मद्देनजर अतिरिक्त प्रबंध किए जा रहे हैं। संस्थान के परिसर, हॉस्टल एवं पीजी और इनके आस-पास के क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार जागरुकता पोस्टर एवं बोर्ड लगाए हैं व इनमें सभी प्रमुख अधिकारियों एवं हेल्पलाइन के नंबर प्रदर्शित किए गए हैं, ताकि इन नंबरों पर रैगिंग की शिकायत की जा सके। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. रमेश भारती का कहना है कि एंटी रैगिंग समिति के सदस्यों को हॉस्टलों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से भी गश्त बढ़ाने का आग्रह किया।

प्रशासनिक कारणों से जेबीटी भर्ती की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया स्थगित

हमीरपुर | हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा पोस्ट कोड-26015 के तहत आयोजित जेबीटी भर्ती की कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दी गई है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन का कहना है कि इन अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 सितंबर से आरंभ होने थी, लेकिन अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नया शेडयूल शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।

मांग • मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केंद्र के सामने उठाए प्रदेश के मुद्दे

प्रदेश को वैज्ञानिक ड्रेजिंग की अनुमति व बिजली प्रोजेक्टों में प्रदेश का अधिकार जल्द दे केंद्र: सुक्खू

भास्कर न्यूज | शिमला

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर हिमाचल से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से अलग-अलग हुई बैठकों में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित नदियों में ड्रेजिंग, बिजली परियोजनाओं में हिमाचल के अधिकार, शानन प्रोजेक्ट, मुफ्त बिजली और बीबीएमबी की खाली जमीन समेत लंबित मामलों के जल्द समाधान की मांग की।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने बाढ़ के बाद नदियों में जमा होने वाले मलबे और पत्थरों को हटाने के लिए वैज्ञानिक ड्रेजिंग की अनुमति देने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के कारण नदियों में बड़ी मात्रा में मलबा जमा हो जाता है। इससे नदी की जलधारण क्षमता कम होती है और आसपास के गांवों, सड़कों व पुलों पर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट नियम बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद नदी से मलबा हटाने के काम को सामान्य खनन गतिविधि से अलग माना जाना चाहिए। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय के परिवेश पोर्टल पर अलग श्रेणी बनाने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से हिमाचल की बिजली परियोजनाओं से जुड़े पुराने और लंबित मामलों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने हिमाचल को मिलने वाले मुफ्त बिजली हिस्से के बदले नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र देने का मामला उठाया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम के निदेशक मंडल में हिमाचल की ओर से दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति जल्द करने की मांग की। इसके अलावा शानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल को सौंपने का मुद्दा भी उठाया गया। यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जमीन का इस्तेमाल सरकारी कार्यालय बनाने और परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र हिमाचल की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्य से जुड़े इन मामलों का जल्द समाधान जरूरी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।

क्षतिपूरक वनीकरण की शर्त में छूट का आग्रह

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव से मिलकर सीएम ने रखा पक्ष।

मुख्यमंत्री ने ड्रेजिंग के मामलों में क्षतिपूरक वनीकरण की शर्त में छूट देने की मांग भी रखी। उनका कहना था कि नदी से मलबा हटाने का काम वन भूमि का इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि नदी का रास्ता साफ करने और बाढ़ का खतरा कम करने के लिए किया जाता है। ड्रेजिंग वैज्ञानिक रिपोर्ट और तय योजना के आधार पर ही की जाएगी तथा इसे गैर-मानसून अवधि में कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिमाचल की मांगों पर सकारात्मक विचार करने और ड्रेजिंग से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने का आश्वासन दिया।

केंद्रीय वित्तमंत्री से ऋण सीमा बढ़ाने का आग्रह

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर प्रदेश की ऋण सीमा तीन से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का आग्रह किया। उन्होंनें प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद होने से पैदा हुई आर्थिक स्थिति से अवगत करवाया और केंद्र से उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीजी प्रदेश को मिलने वाला संवैधानिक अधिकार था। इसके बंद होने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से इस नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देने की मांग की।

हिमाचल की साक्षरता दर 99.5 प्रतिशत पहुंची

पूर्ण साक्षरता हासिल करने पर प्रदेश को मिला राष्ट्रीय सम्मान

दिल्ली में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्राप्त किया पुरस्कार

भास्कर न्यूज | शिमला

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश को लगभग पूर्ण साक्षरता हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस समारोह में प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश 99.5 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ देश में गोवा के बाद दूसरे स्थान पर है।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आजादी के समय जहां प्रदेश की साक्षरता दर मात्र 5 प्रतिशत थी, वहीं आज 99.5 प्रतिशत तक पहुंचना एक बड़ी सफलता है। उन्होंने इसका श्रेय प्रदेश के संस्थापक मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार की दूरदर्शिता और सरकारों द्वारा लगातार शिक्षा में किए गए निवेश को दिया। 1960 और 70 के दशक में सीमित संसाधनों के बावजूद बजट का 18 से 20 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाता था।

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब साक्षरता चुनौती नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए शैक्षणिक व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप कम करने, शिक्षकों के लिए पारदर्शी तबादला नीति बनाने और सत्र के बीच तबादले रोकने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कम छात्र संख्या के कारण प्रदेश में करीब 1500 स्कूलों को बंद या मर्ज करना पड़ा है, इसलिए शिक्षण संस्थान राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि जरूरत के अनुसार खोले जाने चाहिए।

साक्षरता दर का ऐतिहासिक सफर

आजादी के समय हिमाचल की साक्षरता दर मात्र 5% थी (राष्ट्रीय औसत 13%), जो आज बढ़कर 99.5% हो चुकी है। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्राथमिक से 12वीं तक कुल 8.09 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं, जिनमें प्राथमिक स्तर पर 2.99 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हैं।

146 स्कूलों को मिली सीबीएसई संबद्धता

गुणवत्ता सुधार के लिए प्रदेश के 156 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से जोड़ने का लक्ष्य है, जिनमें से 146 स्कूलों को संबद्धता मिल चुकी है। इन स्कूलों में कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकायों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं और राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जा रहा है।

---

150 से अधिक लोग जुटे आर्या की तलाश में, 50 घंटे बाद भी सुराग नहीं

एनडीआरएफ व पुलिस के साथ 4 पंचायतों लोग कर रहे तलाश

हरिपुरधार | नौहराधार तहसील की ग्राम पंचायत लानाचेता के घेवना गांव से रविवार शाम लापता हुई 5 वर्षीय मासूम आर्या का 50 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। मंगलवार को एनडीआरएफ की टीम ने भी मोर्चा संभालते हुए घने जंगलों, गहरी खाइयों, खड्डों और दुर्गम क्षेत्रों को ड्रोन कैमरों की मदद से खंगाला, लेकिन देर शाम तक बच्ची का कोई पता नहीं चल सका। मंगलवार सुबह से ही एनडीआरएफ, पुलिस, प्रशासन और ग्रामीणों की टीमें बच्ची की तलाश में जुटी रहीं। तहसीलदार नौहराधार विनोद कुमार की मौजूदगी में पुलिस जवानों ने भी कई संभावित स्थानों पर सर्च अभियान चलाया। तलाश में स्पेशल डॉग स्क्वॉड की मदद भी ली गई। भौगोलिक परिस्थितियां बेहद कठिन होने के कारण कई दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की गई। लानाचेता पंचायत के साथ-साथ सैर तेंदुला, कुफ्तू, पबौर सहित आसपास के गांवों से सैकड़ों ग्रामीण भी मासूम की तलाश में जुटे हुए हैं। ग्रामीणों की अलग-अलग टीमें जंगलों, बीहड़ रास्तों, नालों और खड्डों में लगातार तलाश कर रही हैं। मंगलवार शाम करीब 6 बजे तक अभियान चलाया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। अब बुधवार सुबह दोबारा बड़े स्तर पर तलाश अभियान शुरू किया जाएगा। विपिन कुमार की 5 वर्षीय बेटी आर्या रविवार शाम करीब 4 बजे घर के आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गई। परिजनों ने रातभर अपने स्तर पर बच्ची को आसपास तलाशा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

तीन दिन से लापता है मासमू आर्या

साढ़े तीन साल में किए करोड़ों के विकास कार्य, सुन्नी में जल्द खुलेगा एचआरटीसी का सब डिपो: विक्रमादित्य सिंह

चलौंठी में पंचायत प्रतिनिधियों के अभिनंदन समारोह में बोले मंत्री

शिमला | ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान 800 करोड़ से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री और शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को चलौंठी स्थित जिला परिषद भवन में पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के अभिनंदन समारोह में यह जानकारी दी। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों, बीडीसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों तथा जिला परिषद सदस्यों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से 2022 तक शिमला ग्रामीण में करीब 100 करोड़ के विकास कार्य करवाए। मंत्री ने कहा कि सुन्नी में हिमाचल पथ परिवहन निगम का सब डिपो जल्द स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का काम किया जा रहा है।

जनप्रतिनिधियों के साथ मंत्री विक्रमादित्य सिंह।

सड़कों की टारिंग और मरम्मत के लिए 850 करोड़ रु. स्वीकृत किए

सब डिपो खुलने से ग्रामीण क्षेत्रों में बस सुविधा बढ़ने की उम्मीद है और लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेशभर में सड़कों की टारिंग और मरम्मत के लिए 850 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बरसात समाप्त होने के बाद सड़कों पर टारिंग और पैच वर्क का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जिन सड़कों पर टारिंग का काम नहीं हो पाया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाएगा।

बद्दी पुलिस की पीओ सेल टीम ने पकड़ा उद्घोषित अपराधी

नालागढ़ | बद्दी पुलिस के पीओ सेल ने एक मामले में वांछित आरोपी सन्नी निवासी ग्राम व डाकघर धनारी तहसील गन्नौर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। न्यायालय कसौली द्वारा आरोपी को उद्घोषित अपराधी घोषित किया था। आरोपी को मंगलवार को न्यायालय कसौली में पेश किया। आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

प्रदेश में थम गया है विकास, नई सरकार बनते ही मिलेगी गति: जयराम

मंडी | पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को अपने सराज विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थाची में आयोजित जोनल अंडर-19 बालिका खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभावान बालिकाओं को ट्रोफियां और पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। जनसमुदाय व खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने दुर्भाग्य से कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने इन चार वर्षों में भेदभाव को बढ़ावा देकर भाजपा विधायकों के हलकों को विकास से महरूम रखा है। आज पूरे हिमाचल में विकास की रफ्तार थम चुकी है। चारों तरह हाहाकार मचा हुआ है। हर वर्ग की अनदेखी हो रही है। अब तो नई सरकार बनते ही विकास को गति मिलेगी और इस इलाके में भी रुके हुए सभी काम पूरे किए जाएंगे। इससे पूर्व उन्होंने लंबाथाच में सराज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की।

ऊना • पूर्व सैन्य अधिकारी ने लगाए फर्जीवाड़े के आरोप

सेरीकल्चर विभाग में करोड़ों के घोटाले का आरोप, सीबीआई जांच की मांग

ऊना | ऊना में रेशम कीट पालन (सेरीकल्चर) विभाग में कथित भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारी मनोज कुमार कौशल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विभागीय योजनाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की आशंका जताते हुए पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है।

मनोज कौशल।

कौशल के अनुसार, विभागीय रिकॉर्ड में 17 रीमिंग यूनिट्स दर्शाई गई हैं, जबकि धरातल पर केवल एक ही यूनिट संचालित है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन गैर-मौजूद कागजी यूनिट्स के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपये की सरकारी सब्सिडी और रिवॉल्विंग फंड जारी किया गया। इसके अलावा, फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र तैयार कर करीब आठ लोगों को डेवलपमेंट ऑफिसर और सेरीकल्चर ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां दी गईं। पूर्व सैन्य अधिकारी ने शिमला में तैनात डिप्टी डायरेक्टर (सेरीकल्चर) समेत अन्य अधिकारियों की भूमिका और उनकी संपत्तियों की जांच की मांग भी उठाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत भेजकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों की बर्खास्तगी और गबन किए गए सरकारी धन की वसूली की मांग की है।

भास्कर खास — 1807 से अब तक के 30 हजार से अधिक दुर्लभ रिकॉर्ड होंगे ऑनलाइन

प्रदेश के इतिहास का संरक्षण... 17 लाख पन्नों का हुआ डिजिटलीकरण, जल्द लॉन्च होगा पोर्टल

भास्कर न्यूज | शिमला

प्रदेश के समृद्ध इतिहास को सहेजने तथा उसे भावी पीढ़ियों तक आसानी से पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। प्रदेश के राज्य अभिलेखागार ने अपने पास सुरक्षित ऐतिहासिक दस्तावेजों के लगभग 17 लाख पन्नों का डिजिटलीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

दुर्लभ रिकॉर्ड्स को आम जनता, शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और छात्रों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक समर्पित 'डिजिटल आर्काइव पोर्टल' तैयार किया जा रहा है। इसे जल्द लॉन्च किया गया है। इस महत्वपूर्ण पहल के शुरू होने के बाद लोगों को अब पुराने इतिहास और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े दस्तावेजों को खंगालने के लिए अभिलेखागार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोग एक क्लिक पर प्रामाणिक और ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे।

डिजिटल आर्काइव की प्रमुख विशेषताएं और दूरगामी लाभ

- **1807 से अब तक का रिकॉर्ड सुरक्षित:** राज्य अभिलेखागार में 1807 से लेकर अब तक के 30 हजार से अधिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनमें दुर्लभ पुस्तकें, गजेटियर, सेटलमेंट रिपोर्ट, ऐतिहासिक पांडुलिपियां और प्रशासनिक इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं।
- **आसान खोज के लिए सर्चेबल डेटा:** तैयार किए गए डिजिटल रिकॉर्ड को आधुनिक तकनीक से 'सर्चेबल' बनाया जा रहा है। इससे शोधकर्ताओं और अध्ययनकर्ताओं को किसी विशिष्ट विषय, वर्ष या दस्तावेज को खोजने में समय नहीं गंवाना पड़ेगा और वे कम समय में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- **पांडुलिपियों का व्यापक संरक्षण:** केवल अभिलेखागार ही नहीं, बल्कि प्रदेश की पुरानी पांडुलिपियों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से 'ज्ञान भारतम् मिशन' के तहत प्रदेश भर में दुर्लभ पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए शिमला स्थित हिमाचल राज्य संग्रहालय में क्लस्टर सेंटर स्थापित किया गया है।
- **ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा:** उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कागजी दस्तावेजों को डिजिटल स्वरूप में बदलने से इन्हें समय के साथ खराब होने या फटने से बचाया जा सकेगा। इससे मूल प्रतियों का रख-रखाव आसान होगा।

pnb punjab national bank
...the name you can BANK upon!

ई-नीलामी / बिक्री सूचना

सर्कल ऑफिस SAM: मंडी (हि.प्र.) पता: पीएनबी सर्कल ऑफिस, खलियार, मंडी हि.प्र.-175001, संपर्क नंबर 01905-222094, ईमेल- cs8276@pnb.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीख और समय संपत्ति क्रम संख्या 1 के लिए 24-09-2026 दोपहर 3:00 बजे तक और संपत्ति क्रम संख्या 2 से 3 के लिए 06-10-2026 दोपहर 3:00 बजे तक तक है।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना,
एतद्द्वारा सर्वसाधारण और विशेष रूप से ऋणी (ऋणियों) एवं जमानतदार (ऋणियों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, संबंधित ऋणी (ऋणियों) एवं जमानतदार (ऋणियों) से बैंक/सुरक्षित ऋणदाता को देय बकाया राशि की वसूली हेतु, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को 'जैसी है जहाँ है', 'जैसी है जो है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा एवं खाता का नाम	संपत्ति/परिसंपत्ति के मालिक का नाम	संपत्ति / परिसंपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / ईएमडी (आरक्षित मूल्य का 10%) / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि और समय	मांग सूचना की तिथि/ बकाया राशि/ कब्जे की तिथि
1	पंजाब नेशनल बैंक आनी जिला कुल्लू (हि.प्र.) श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री मंगत राम (उधारकर्ता) खाता संख्या 097500NC00010913 और 097500NC00013451	श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री मंगत राम	शारदा देवी के भूमि एवं भवन का पंजीकृत बंधक में शामिल खाता खतौनी संख्या 920/1094 खसरा संख्या 2796 माप 0-03-0 बीघा जो कुल भूमि माप 02-09-0 बीघा का 36/588 का हिस्सा है। जो जमाबंदी वर्ष 2015-16 के अनुसार, की कुल भूमि में से हिस्सा फाटी मंझदेश तहसील आनी जिला कुल्लू हि.प्र. में स्थित है।	रूपए 49,00,000/- / रूपए 4,90,000/- / रूपए 50,000/-	24-09-2026 सुबह 11.00 बजे से 04.00 सायं	13(2) दिनांक 10.02.2026 बकाया राशि रूपए 24,21,752.36/- (केवल चौबीस लाख इक्कीस हजार सात सौ बावन रुपये और छत्तीस पैसे) के साथ, 01.02.2026 से आगे का ब्याज, एवं अन्य शुल्क, जिसमें से वसूली गई राशि घटा दी गई है। सांकेतिक कब्जे की तिथि: 25.05.2026
2	पंजाब नेशनल बैंक आनी जिला कुल्लू (हि.प्र.) श्री भूषण लाल सुपुत्र श्री हेत राम (उधारकर्ता) खाता संख्या 097500NC00011897	श्री भूषण लाल सुपुत्र श्री हेत राम	भूषण लाल (बंधककर्ता/उधारकर्ता) की भूमि और भवन का पंजीकृत बंधक, माप 00-02-00 बीघा, जो कुल भूमि माप 25-12-00 का 2/512 हिस्सा है, खाता और खतौनी संख्या 794/970 किता के अधीन फटी करशाईगढ़ उप-तहसील आनी जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है।	रूपए 5,51,000/- / रूपए 55,100/- / रूपए 10,000/-	06-10-2026 सुबह 11.00 बजे से 04.00 सायं	13(2) दिनांक 07.02.2020 बकाया राशि रूपए 4,95,554/- (केवल चार लाख पचानवे हजार पाँच सौ चौवन रुपये) के साथ, 01.01.2025 से आगे का ब्याज, एवं अन्य शुल्क, जिसमें से वसूली गई राशि घटा दी गई है। भौतिक कब्जे की तिथि: 23.08.2022
3	पंजाब नेशनल बैंक आनी जिला कुल्लू (हि.प्र.) श्रीमती कांता धीमान पत्नी श्री लच्छी राम (उधारकर्ता) खाता संख्या 097500NC00013512	श्रीमती कांता देवी पुत्री मेहर चंद	कांता देवी पुत्री मेहर चंद की भूमि और भवन का पंजीकृत बंधक खाता खतौनी नंबर 1545/1787, खसरा नंबर 1955 के तहत शामिल है, माप 0-03-05 बीघा कुल भूमि 0-13-0 बीघा का 1/4 हिस्सा जो जमाबंदी वर्ष 2015-2016 के अनुसार थुआर फाटी मंझदेश तहसील आनी जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है	रूपए 23,00,000/- / रूपए 2,30,000/- / रूपए 30,000/-	06-10-2026 सुबह 11.00 बजे से 04.00 सायं	13(2) तारीख: 16-06-2025 बकाया राशि रूपए 23,61,366.82/- (तेइस लाख इकसठ हजार तीन सौ छयासठ रुपये एवं ब्याज्ञी पैसे मात्र) और 01.06.2025 से आगे का ब्याज और अन्य शुल्क तथा वसूली घटाकर सांकेतिक कब्जा की तारीख 15-11-2025

स्थानीय निकाय /राज्य/केंद्र सरकार को देय बकाया बैंक को पता नहीं है।
बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए: कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

कर्जदार/गारंटरों को सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तारीख से पहले ऊपर बताई गई बकाया राशि के साथ-साथ आज तक का ब्याज और अन्य खर्चों का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि होगी तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

स्थान: मंडी (हि.प्र.) तारीख: 08.09.2026 अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, सीओ एसएएम, सीओ मंडी हि.प्र.